न्यूज डायरी

ताइवान के हवाई क्षेत्र में फिर घुसे चीन के 27 लड़ाकू विमान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) ताइपे। चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ किया है। जिसके बाद गुस्साए ताइवान ने इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रविवार को ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के शीर्ष जनरलों से मुलाकात की थी। चीनी लड़ाकू विमानों हालिया घुसपैठ को ताइवान की खाड़ी में बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 27 विमानों ने रविवार को उसके एयर डिफेंस बफर जोन में प्रवेश किया। चीन की इस हरकत का जवाब देते हुए हमने भी अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर चीनी विमानों को चेतावनी दी। मंत्रालय ने बताया कि हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वालों में 18 लड़ाकू विमान, पांच एच–6 बमवर्षक विमान और ईंधन भरने वाला एक वाई–20 शामिल था।

ब्रिटेन का दावा परीक्षण के अंतिम स्टेज पर वैक्सीन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान के खिलाफ दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस वैरिएंट को 'वैरिएंट आफ कंसर्न' की श्रेणी में रखे जाने के साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने एक नई वैक्ल्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे इस संकट से उबरने की एक नई उम्मीद जगी है। इस संकट के बीच ब्रिटेन से एक राहत देने वाली एक खबर सामने आई है। ब्रिटेन ने यह दावा किया है कि सुपर म्यूटेंट कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देने वाली एक ब्रिटिश वैक्सीन पहले से ही अपने परीक्षण के अंतिम स्टेज पर है। कोरोना के नए संस्करण के बारे में विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं ने वैक्सीन के विकास पर अपनी प्रतिक्रिया को साझा किया है। इसमें फाइजर/बायोएनटेक, माडर्न, एस्ट्राजेनेका, जानसन एंड जानसन और नोवावैक्स प्रमुख है।

ब्रिटेन को बड़ा झटका देने की तैयारी में चीन, कॉमनवेल्थ देशो को कर्ज से पाट रहा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बीजिंग। चीन ने ब्रिटेन से जारी तनाव के बीच बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। चीन ने पिछले 16 साल में ब्रिटेन के प्रभाव वाले 42 राष्ट्रमंडल देशों में 913 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। राष्ट्रमंडल देशों में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर ब्रिटेन सकते में है। ब्रिटेन और चीन के बीच हॉन्ग कॉन्ग, उइगुर और ताइवान को लेकर पहले से ही विवाद है। राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं, जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने आंकड़ों के आधार पर बताया है कि चीन ने 2005 से अब तक 42 राष्ट्रमंडल देशों में 913 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसमें कैरिबियाई देश बारबाडोस और जमैका भी शामिल हैं। सोमवार को गणतंत्र बनने के लिए तैयार बारबाडोस में चीन ने 667 मिलियन डॉलर जबकि पड़ोसी जमैका में 3.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

लेबर पेन में साइकिल चलाकर हॉस्पिटल पहुंची न्यूजीलैंड की यह महिला सांसद

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की सांसद जूली एनी जेंटर ने रविवार को प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) में साइकिल से अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल पहुंचने के एक घंटे बाद बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची और मां दोनों स्वस्थ हैं। जूली एनी जेंटर न्यूजीलैंड की ग्रीन पार्टी से सांसद हैं। जेंटर अमेरिका के मिनिसोटा में पैदा हुईं थी। 2006 में वह न्यूजीलैंड में आकर बस गईं। उनक पास ब्रिटेन और अमेरिका की दोहरी नागरिकता भी है। ग्रीन पार्टी की सांसद जूली एनी जेंटर ने बच्ची के जन्म के बाद फेसबुक पर लिखा कि ष्बड़ी खबर! आज सुबह 3.04 बजे हमने अपने परिवार के सबसे नए सदस्य का स्वागत किया। मैं वास्तव में लेबर पेन में साइकिल चलाने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन अंत में यही हुआ। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में पहले से ही जमीन से जुड़े राजनेताओं की काफी प्रतिष्ठा है।

भूटान पर सीमा विवाद को लेकर धौंस जमा रहा चीन

चीन का भूटानी जमीन पर गांवों के निर्माण से भारत की टेंशन बढ़ी

चिंता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

बीजिंग। चीन ने सीमा विवाद को लेकर अब अपने से कहीं ज्यादा छोटे देश भूटान को धमकाना शुरू कर दिया है। 1984 से भूटान के साथ बातचीत करने के बावजूद चीन अभी तक सीमा विवाद को सुलझाने में विफल रहा है। अब लगभग चार दशकों बाद चीन ने एक बार फिर भूटान के साथ सीमा वार्ता को तेज करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ढोल पीट रहा है। कुछ दिन पहले ही खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान की जमीन पर कम से कम चार गावों का निर्माण किया है। इस इलाके में चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्टर से भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है।

चीन का सिर्फ भारत और भूटान के साथ सीमा विवादः चीन की 22457 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगी है लेकिन सिर्फ भारत और भूटान के साथ ही उसका सीमा विवाद है। भूटान और चीन के बीच

477 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन और भूटान सीमा पर मुख्य रूप से दो इलाके ऐसे हैं, जिसपर विवाद ज्यादा है। भूटान के साथ समझौता ज्ञापन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि दूसरों की जमीन कब्जाने की ताक में बैठे चीन ने दुनिया के सबसे कम आबादी और सैन्य नेतृत्व रूप से कमजोर मुल्क की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है।

भूटान से चीन क्या चाहता है?: चीन हर हाल में भूटान के साथ सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है। इसके जरिए वह पूरी दुनिया को झूठा संदेश देने की कोशिश में है कि सिर्फ भारत के साथ ही उसका सीमा विवाद है और वह भारतीय नेताओं की हठधर्मिता के कारण समझौता नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, चीन चाहता है कि भूटान तिब्बत से सटे एक बड़े भूभाग को ले ले और इसके बदले में डोकलाम के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके को उसे सौंप दे। भारत जानता है कि अगर भूटान ने यह इलाका चीन को सौंपा तो इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है।

चीन–भूटान समझौते से भारत की मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी?: दरअसल, चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक भूटानी जमीन पर सड़कों और सैन्य प्रतिष्ठानों का जाल सा बुन दिया है। चीन का यह निर्माण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है। इतना ही नहीं, यह इलाका डोकलाम के नजदीक है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच कई महीनों तक सैन्य तनाव बना हुआ था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। यह गलियारा ही शेष भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ जोड़ता है। यह कॉरिडोर तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटा हुआ है। कई जगहों पर इस कॉरिडोर की चौड़ाई बमुश्किल 22 किलोमीटर की है।

गलवान हिंसा के बाद भारत सतर्क गलवान में हिंसा और लद्दाख में जारी तनाव के बाद भारत सतर्क है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर कई बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में भारतीय सेना की माउंटेन कोर, हल्के तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, ठंड में सुरक्षा प्रदान करने वाले टेंट समेत कई एहतियाती कदम उठाए हैं।

हमपर हमला करने से पहले अपनी ताकत जांच लेना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

तेहरान। ईरान और इजरायल में जारी तनाव के बीच धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद एस्लामी ने अपने परमाणु केंद्रों पर हमले की धमकी को लेकर इजरायल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने यमनी टेलीविजन नेटवर्क अल–मसीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजरायल पहले खुद को आईने में देखे और धमकी देने से पहले अपनी क्षमताओं की जांच कर ले।

इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर इजरायल इस्लामिक गणराज्य पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसे गंभीर आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। शामखानी ने ट्वीट कर कहा था कि ईरान के खिलाफ अत्याचारों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का बजट आवंटित करने के बजाय यहूदी शासन को ईरान की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दसियों हजार बिलियन डॉलर की फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

दरअसल, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया था कि इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की तैयारी के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी थी।

5200 मीटर की ऊंचाई पर डांस कर रहे चीनी सैनिक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बीजिंग। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों का 5200 मीटर की ऊंचाई पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। 16 सेकेंड के इस वीडियो को चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हू चुनयिंग ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट कर कैप्शन में लिखा ष्कूल एंड क्यूट! इसके बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से शेयर किया जा रहा है। चीनी सैनिक इन दिनों हिमालयी रीजन में हाई एल्टिट्यूड सिकनेस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि चीन को इतनी ऊंचाई पर सैनिकों का प्रॉपगैंडा वीडियो जारी करना पड़ा है। हालात तो यहां तक बिगड़ गए थे कि चीन को सीमा पर अग्रिम इलाकों में तैनात अपने सभी सैनिकों को बदलना पड़ा था।

भारत में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर यूएन ने जताई खुशी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष मानवाधिकार विशेषज्ञ ने विवादित तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आशा जताई कि कृषि सुधारों के संबंध में भविष्य में लिए जाने वाले फैसले देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे और किसानों, समुदायों और संघों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद लिए जाएंगे। भारत सरकार ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून वापसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा

मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत के फैसले पर जताई खुशी

लिया है।

पीएम मोदी ने 19 नवंबर को किया था ऐलानः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती, 19 नवंबर, के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि किसान इन कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं।

आंदोलन खत्म कर लोगों से घर वापस जाने की अपील पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि ये कानून किसानों के हित में थे और सरकार साफ दिल और साफ नियत होने के बावजूद यह बात किसानों के एक धड़े को नहीं समझा सकी। जिसके बाद उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म कर घर जाने की अपील भी की।

यूएन के विशेष दूत ने जताई खुशीः भोजन के अधिकार मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत माइकल फाखरी ने कहा कि इन कानूनों के कारण भारत की पूरी खाद्य व्यवस्था दांव पर लगी थी। आशा करते हैं कि कृषि सुधारों के संबंध में भविष्य में लिए जाने वाले फैसले देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे और किसानों, समुदायों तथा संघों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद लिए जाएंगे।

गुमनाम ट्रोलर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया पेश करेगा कानून

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले यूजर्स की पहचान सामने लाने के लिए एक नया बिल पेश करेंगे। बिल के तहत फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपमानजनक टिप्पणी करने वाले गुमनाम यूजर्स की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। इस बिल से कोर्ट मानहानि के मामलों में मदद के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की पूरी पहचान सौंपने के लिए मजबूर कर सकती है। सोशल मीडिया कंपनियों को उन लोगों के लिए एक शिकायत प्रक्रिया बनाने की जरूरत होगी, जिन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह ऑनलाइन बदनाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि इस हफ्ते बिल ड्राफ्ट फॉर्म में जारी किया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में बिल संसद में पेश हो सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में भी कानून होने चाहिए। ऑनलाइन दुनिया एक जंगली पश्चिम नहीं होनी चाहिए, जहां यूजर्स गुमनाम होकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।